देहरादून, मसूरी एवं सहारनपुर से एक साथ प्रकाशित

दैनिक

♦बढ़ते कदम ऊंचाई की ओर♦

♦देहरादून संस्करण♦

न्यूज़ डिटेल

वर्ष 14, अंक 69 | देहरादून, रविवार 2 फरवरी 2025 | पृष्ठ 8- मूल्य 1.00 रू

देहरादून.....7

लंबित जनगणना के लिए आवंटित किए गए मात्र 574 करोड़ ....

अंदर पृष्ठों पर....

देहरादून.....

....3 विधानसभा अध्यक्ष ने...

राजधानी....

....8 चैंपियन-उमेश कुमार...

RAJ COMMUNICATION
Promote Your Business
Public Relation | Media Monitoring | Digital

Public Relation Agency

RAJ COMMUNICATION

Services: ◆ Public Relations ◆ Press Conference ◆ Media Monitering ◆ Crisis Management ◆ Event Management ◆ Digital PR ◆ Branding ◆ Marketing ◆ Story Telling ◆ Advertising

NETWORK ACROSS INDIA:- Punjab | Haryana | Himachal Pradesh | Uttarakhand | J&K | Delhi | Uttar Pradesh | Bihar | Jharkhand | Madhya Pradesh | Rajasthan | Maharashtra | Gujarat | Pune | Hyderbad
Head Office- 6, Saharanpur Road, Dehradun- 248001 (U.K.) Mob: 7417010666, 7417100666, 9193838389, Website: www.rajcommunication.net, Email: cmd.rajcommunication@gmail.com

केंद्रीय बजट विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी: सीएम

सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत

केंद्रीय बजट से उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिलेगी गति-मुख्यमंत्री धामी

चालू वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों से उत्तराखंड को मिलेगी 444 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि

देहरादून, संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करते हुए देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शानदार और संतुलित बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट से, उत्तराखंड को कई योजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस वर्ष के संशोधित अनुमान में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा लगभग 14387 रुपए करोड होगा। इससे मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश को 444 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आगामी वर्ष हेतु यह राशि लगभग 15902 करोड़ रुपए तक जा सकती है। राज्य के लिए यह राशि अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व सम्मेलन में 11 बिन्दुओं का निवेदन किया था। जिसका समावेश भी बजट में दिख रहा है। इसके लिए, उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है।

जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से अपने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व साइबर सुरक्षा से संबंधित उत्कृष्टता केन्द्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्थापित किये जाने का निवेदन किया था। इस बजट में देश में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की गई है। इसी तरह सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणा प्रदेश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नॉलेज इकॉनोमी के लिए यह एक मजबूत नीव होगी। इसी तरह केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा 2028 तक बढ़ाने के लिए राज्य का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड रुपए कर्ज का प्रावधान किया गया है। यह इस वर्ष के संशोधित अनुमान 1,25,000 करोड से 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। विगत दो वर्षों में इस ब्याजमुक्त योजना से हमारे राज्य को बड़ा लाभ मिला है।

जिलों में होगा कैंसर मरीजों का उपचार: मुख्यमंत्री ने कहा कि 125 शहरों के लिए नई उड़ान योजना शुरू किए जाने का लाभ उत्तराखण्ड को भी मिलेगा। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर सेंटर बनाए जाने से प्रदेश में चिकित्सा सेवा को विस्तार मिलेगा। देश के 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत से प्रदेश के किसान के भी लाभान्वित होने की आशा है। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किये जाने की घोषणा से प्रदेश के किसानों को भी फायदा होगा। इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में परिवर्तित करने से उत्तराखण्ड के दूर-दराज क्षेत्रों में पोस्ट आफिस के माध्यम से आर्थिक गतिशीलता बढेगी।

आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है ऐतिहासिक बजट : महेंद्र भट्ट

देहरादून। भाजपा ने केंद्रीय बजट को आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला ऐतिहासिक बजट बताया है। राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नौकरी पेशा मध्यम वर्ग समेत 80 फीसदी लोगों को टैक्स से दी छूट और टूरिज्म, कृषि क्षेत्र को मिली प्राथमिकता, उत्तराखंड के विकास में अहम साबित होने वाली है। लोकसभा में प्रस्तुत सर्वस्पर्शी एवं सर्वग्राही बजट के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया किया। उन्होंने कहा कि विकास और विरासत के मूलमंत्र पर आधारित यह बजट, विकसित भारत निर्माण की गति तेज करने वाला बजट है। उत्तराखंड के संदर्भ में ही देखें तो राज्य ने नौकरी पेशा एवं माध्यम वर्ग के संख्या बहुत है। ऐसे में मोदी सरकार का 1 लाख रूपए तक प्रति माह औसत आय पर आय कर की छूट से उनको 80 हजार तक की बचत प्रतिवर्ष होगी।

विकसित एवं समृद्ध भारत का बजट: महाराज

देहरादून। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि केन्द्रीय बजट-2025 सकारात्मक, स्वागत योग्य और आम व्यक्ति का बजट है। केन्द्रीय बजट-2025 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ष्ये बजट एक विकसित एवं समृद्ध भारत का बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प का और एक नये ऊर्जावान युवा भारत के सपनों को साकार करने का बजट है। यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

बजट में व्यक्तिगत आयकर स्लैब को तर्कसंगत बनाया गया: साक्षी गुप्ता

देहरादून, संवाददाता। एचडीएफसी बैंक की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मध्यम वर्ग की ओर से मांग में कमी की चिंताओं को संबोधित करते हुए, बजट में व्यक्तिगत आयकर स्लैब को तर्कसंगत बनाया गया है, साथ ही स्रोत पर कर कटौती की सीमा में संशोधन किया गया है। इससे मध्यम वर्ग द्वारा उपभोक्ता मांग और बचत को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिसने उच्च मुद्रास्फीति और कम आय वृद्धि से चुनौतियों का सामना किया है। आम आदमी के लिए रियायतों से परे, बजट लाइट टच नियामक दृष्टिकोण के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। अगले पांच साल की राजकोषीय रणनीति कृषि, एमएसएमई, निर्यात को बढ़ावा देने और भारत की क्षमता निर्माण में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में तैयार की गई है। वित्त मंत्री की राजकोषीय रणनीति खपत को बढ़ावा देने की ओर झुकी हुई है।

बजट में देवभूमि उत्तराखंड के साथ अन्याय: विपुन जैन

देहरादून, संवाददाता। पूर्व मंडी अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता विपुल जैन ने केंद्रीय बजट को उत्तराखंड वासियों के लिए उदासीन बताया है। प्रदेश का युवा प्रदेश को नए औद्योगिक पैकेज ना दिए जाने से नए रोजगार अवसर से फिर वंचित महसूस कर रहा है एवं प्राकृतिक ऊर्जा (हाइडल पॉवर जनरेशन) उत्पादन के लिए भी विशेष बजट से वंचित रखकर उत्तराखंड वासियों को सस्ती बिजली एवं कटौती मुक्त बिजली सप्लाई से वंचित रहना पड़ेगा। उत्तराखंड के वर्तमान जल विद्युत उत्पादन केंद्र नए बजट में प्रावधान ना होने से टेक्निकल अपग्रेडेशन से वंचित रहेंगे एवं बजट अभाव में नए उत्पादन ग्रह का संचालन असंभव होने से महंगी एवं बाधित बिजली सप्लाई को प्रदेश एवं जिला देहरादून वासियों को मजबूर होना पड़ेगा। यह सौतेला व्यवहार देवभूमि उत्तराखंड के साथ अन्याय है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केन्द्रीय आम बजट को दिशाहीन, प्रगतिहीन व विकास अवरोधी बताया

देहरादून, संवाददाता। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने केन्द्रीय आम बजट को दिशाहीन, प्रगतिहीन, विकास अवरोधी तथा आम आदमी के हितों के खिलाफ मंहगाई बढ़ाने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में उत्तराखण्ड की अनदेखी की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने केन्द्रीय आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने अपनी हठधर्मिता का परिचय देते हुए जो आम बजट प्रस्तुत किया है वह दिशाहीन, प्रगतिहीन, विकास विरोधी, बेरोजगारी व मंहगाई बढ़ाने वाला तथा देश की आर्थिक वृद्धि पर चोट पहुंचाने वाला है। यह बजट केवल गठबंधन की सरकार को बचाने वाला बजट है, इसमें केवल बिहार के लिए ही बडी धोषणाए की गई है, कुल मिलाकर यह बिहार का बजट लगता है ना कि देश का बजट। बिहार को छोडकर देश के अन्य राज्यों के लिए यह बजट निराश करने वाला बजट है। देश की वित्त मंत्री ने बजट में आंकडों की बाजीगरी कर घुमाकर नाक पकड़ने का काम किया है। इस बजट से मंहगाई बढ़ने के साथ ही आम आदमी के सिर पर बोझ बढेगा। उन्होंने कहा कि बजट के प्रावधानों से विकास दर दहाई का आंकडा भी नहीं छू पायेगी और न ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

पेयजल प्रदूषित और सवालिया

रोहित छाबड़ा (राज)
संपादक

यह बेहद गंभीर और नाजुक आरोप है, लिहाजा चुनाव आयोग तह तक जाना चाहता है कि जहर कौन-सा था? कब और कैसे यमुना के पानी में मिलाया गया?

यमुना नदी के जहरीले पानी पर दिल्ली चुनाव में वाकई जंग छिड़ी है। इसमें आम आदमी पार्टी (आप), भाजपा ही शामिल नहीं हैं, बल्कि चुनाव आयोग का युद्ध अलग किस्म का है। उसके निशाने पर 'आप' और केजरीवाल हैं। आयोग ने 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल से पांच और सवाल पूछे थे। केजरीवाल ने यहां तक आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाने की साजिश रची थी। यदि दिल्ली सरकार के इंजीनियरों ने विषाक्त पानी को यथासमय न रोका होता, तो दिल्ली में 'नरसंहार' भी हो सकता था। यह बेहद गंभीर और नाजुक आरोप है, लिहाजा चुनाव आयोग तह तक जाना चाहता है कि जहर कौन-सा था? कब और कैसे यमुना के पानी में मिलाया गया? दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने कहां पानी रोका, नतीजतन दिल्ली 'नरसंहार' से बच गई? यमुना के जहरीले पानी पर यह सियासत 5 फरवरी को थम जाएगी, क्योंकि उस दिन दिल्लीवाले नई विधानसभा के लिए मतदान करेंगे, लेकिन इससे भी अधिक संवेदनशील और मानवीय सवाल देश भर में साफ पेयजल को लेकर है। एनएसएसओ के 79वें राउंड का डाटा है कि देश के करीब 95 फीसदी घरों की पहुंच पेयजल तक जरूर है। नल के जरिए जल, संरक्षित कुओं, नलकूपों और बोतलबंद पानी के तौर पर घरों को पीने का पानी उपलब्ध है, लेकिन कोई भी विभाग, एजेंसी या वितरण-संस्था यह शर्तिया दावा नहीं कर सकती कि उपलब्ध पेयजल बिल्कुल साफ, विषाणु-रहित और पीने योग्य पानी है। बेशक 'नल से जल' अभियान के बाद पानी के रंगों में सुधार आया है, लेकिन अभी बहुत कुछ सवालिया और प्रदूषित है। ग्रामीण भारत के करीब 40 फीसदी घरों में पेयजल का मुख्य स्रोत नल का पानी ही है, जबकि शहरों में यह आंकड़ा करीब 70 फीसदी है। इस पेयजल की स्वच्छता, पीने की योग्यता पर सवाल क्यों उठते रहे हैं? हमारा करीब 70 फीसदी पानी 'प्रदूषित' क्यों है? यह सवाल नीति आयोग के 'संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक' की जून, 2018 में प्रकाशित रपट में सामने आया है।

रपट में यह भी उल्लेख किया गया है कि पानी की गुणवत्ता के संदर्भ में भारत दुनिया के 122 देशों में 120वें स्थान पर है। यह सवालिया के साथ-साथ शर्मनाक स्थिति है। अनुमान है कि 4 करोड़ अपशिष्ट पानी हररोज हमारी नदियों और अन्य जल-स्रोतों में मिलता है। उसमें से एक छोटा-सा हिस्सा ही शोधित किया जाता है। जब शोधन किए गए पानी को पाइपों के जरिए प्रवाहित किया जाता है, तो उस पानी की गुणवत्ता भी दूषित हो जाती है, क्योंकि पानी को पुराने नेटवर्क के जरिए ही प्रवाहित किया जाता है। उस नेटवर्क के समानांतर सीवेज लाइनें होती हैं, लिहाजा पानी के प्रदूषित होने की संभावनाएं सौ फीसदी होती हैं। निष्कर्ष है कि जो पानी नलों के जरिए दिन में कुछ समय के लिए ही छोड़ा जाता है, वह पीने लायक नहीं रह पाता। क्षेत्र और आवासीय कालोनी के मुताबिक भी पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। 2019 में मुंबई के नल वाले जल को 100 फीसदी सुरक्षित घोषित किया गया था, लेकिन मॉनसून मौसम से पहले ही शहर में जल संबंधी बीमारियां बढ़ने लगीं। हमारे राजनेता और सत्ताएं बिल्कुल परवाह नहीं करतीं। चुनाव कभी भी पानी के मुद्दे पर तय नहीं हुए। शुक्र है कि इस बार दिल्ली चुनाव में यमुना का पानी अचानक सबसे उग्र चुनावी मुद्दा बन गया है। यमुना के पानी को शोधित करने के लिए संयंत्र कार्यरत हैं, लेकिन पानी में अमोनिया अथवा अन्य रसायन की उपस्थिति मात्रा से अधिक होगी, तो संयंत्र भी पानी को पीने लायक नहीं बना सकते। बेशक देश की राजधानी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सरीखे वीवीआईपी के अलावा न्यायाधीश, सांसद, राजनयिक भी रहते हैं।

प्रदेश के संदर्भ में ओबीसी आरक्षण

कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर ओबीसी और संविधान की बात करते हैं, लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार ने 93वें संविधान संशोधन को लागू नहीं किया, जिससे उनकी बातों की अनदेखी की जा रही है...

भारत में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है, जिसका उद्देश्य समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। यह प्रावधान न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों का पालन भी करता है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित विवाद और समस्याएं इसे एक संवेदनशील और जटिल विषय बना चुकी हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां इस प्रावधान का सही तरीके से पालन नहीं हो पाया है। ओबीसी आरक्षण का उद्देश्य केवल जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना है। यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें, ताकि वे शिक्षा, रोजगार और विकास के क्षेत्र में समान रूप से भागीदार बन सकें, भारतीय संविधान का एक मुख्य उद्देश्य है। हालांकि, हिमाचल प्रदेश में इस उद्देश्य को लागू करने में कई बाधाएं सामने आई हैं, जो ओबीसी वर्ग के उत्थान के रास्ते में रुकावट डालती हैं। हिमाचल प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का कार्यान्वयन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है।

राज्य में 48 ओबीसी जातियां एवं चार क्षेत्र जिओग्राफिकल बैकवर्डनेस के कारण जिसमें ज्यादातर अपर कास्ट समुदाय के लोग ओबीसी में शमिल हैं। लेकिन इन जातियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन वास्तविकता में यह आंकड़ा केवल 12-18 प्रतिशत के बीच है। शैक्षिक क्षेत्र में भी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है, जो उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक बड़ी बाधा बन गई है। वर्ष 2006 में, केंद्र सरकार ने 93वें संविधान संशोधन को लागू किया था, जिसके तहत सभी सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। हालांकि, लगभग दो दशकों के बाद भी, हिमाचल प्रदेश में सरकारों ने इस संशोधन को लागू नहीं किया। यह राज्य सरकारों की नीति निर्धारण में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर, 2019 में राज्य सरकार ने 103वें संविधान संशोधन को तत्काल लागू किया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण प्रदान किया गया, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर कोई प्रगति नहीं हुई। यदि उस समय 93वें संविधान संशोधन को भी लागू किया जाता, तो यह एक ऐतिहासिक कदम होता और समाज में न्याय की दिशा में भाजपा सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास साबित होता। मैंने इस मुद्दे को न केवल विधानसभा में, बल्कि व्यक्तिगत रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाया। बावजूद इसके, पार्टी और मुख्यमंत्री की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। आज भी, हिमाचल प्रदेश के शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी वर्ग को कोई विशेष आरक्षण नहीं मिल रहा है। राज्य विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के लिए आरक्षण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के लिए केवल दो सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों में यह संख्या शून्य है। उदाहरण स्वरूप, प्रदेश के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय में ओबीसी वर्ग को छोड़कर सभी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। चौधरी सरवण कुमार के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय में ओबीसी समुदाय के विद्यार्थियों को दाखिला पाने के लिए कोई आरक्षण नहीं है, जो कि न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि हास्यास्पद भी है। कृषि क्षेत्र में ओबीसी का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में आरक्षण के अभाव ने उन्हें अवसरों से वंचित किया है। इसके परिणामस्वरूप, ओबीसी वर्ग के लोग शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर करता है। भारतीय संविधान के तहत ओबीसी आरक्षण का प्रावधान समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था। यह व्यवस्था 93वें संविधान संशोधन (2006) के तहत लागू हुई, जिसके बाद ओबीसी के लिए आरक्षण को संवैधानिक दर्जा मिला। हालांकि, इस उद्देश्य को लागू करने में कई राज्य सरकारें असफल रही हैं, लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है कि ओबीसी आरक्षण को सही तरीके से लागू किया जाए। केवल तभी समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिल सकेंगे, और ओबीसी वर्ग अपनी शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार कर सकेगा। ओबीसी आरक्षण की आवश्यकता भारतीय समाज में तब तक बनी रहेगी, जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थिति पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाती। यह संवैधानिक प्रावधान केवल एक अस्थायी उपाय नहीं, बल्कि समाज में न्याय, समानता और अवसरों की समानता सुनिश्चित करने का एक स्थायी रास्ता है। हिमाचल प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

रमेश धवाला, पूर्व मंत्री

हिमाचली पहाड़ी भाषा

हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी-बड़ी रियासतों को मिलाकर अस्तित्व में आया। इसे देश का पहाड़ी राज्य कहा जाता है। यहां पहाड़ी शब्द को दो मायनों में समझा जा सकता है। पहला कि हिमाचल पश्चिमी हिमालय में हिम के आंचल में बसा हुआ है, तथा इसका अधिकतर भूक्षेत्र पर्वतों व पहाड़ों से घिरा है। इसलिए इसे देश के पहाड़ी राज्य की संज्ञा दी गई। लेकिन देश में हिमाचल केवल एकमात्र राज्य नहीं है, जो भौगोलिक रूप से पहाड़ों एवं पर्वतों से घिरा है, इसके अलावा प्रदेश के साथ लगते पड़ोसी राज्य उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर के साथ देश के पूर्वोतर राज्य भी लगभग हिमाचल के माफिक भौगोलिक विधाएं समेटे हुए हैं। अत~ हिमाचल को भौगोलिक आधार से देश का केवल एकमात्र पहाड़ी राज्य मान लेना तर्कसंगत होगा। वहीं दूसरा तथ्य प्रदेश में बोले जाने वाली बोली एवं भाषा के संदर्भ में है। प्रदेश में पहाड़ी भाषा का प्रचलन रहा है। यूं कहें कि पहाड़ी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाओं एवं बोलियों को पहाड़ी भाषा कहा गया। भाषाविदों के अनुसार यहां की पहाड़ी भाषा को, पश्चिमी पहाड़ी की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है तथा जिसकी लिपि को मुख्यत~ शारदा व टांकरी माना गया है। अत~ भाषा के आधार पर हिमाचल में बोली जाने वाली भाषा पहाड़ी होने के कारण ही शायद इन्हें पहाड़ी राज्य का तमगा मिला है, ऐसा कहने में अतिशयोक्ति न होगी। पड़ोसी राज्य जम्मू-कश्मीर की भाषा के संदर्भ में बात करें तो यहां मूलत~ कश्मीरी व डोगरी का प्रचलन है, जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में वर्णित किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो असम राज्य में असमी, बोड़ो व बंगाली आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। मणिपुर में मणिपुरी व अंग्रेजी, मेघालय में अंग्रेजी व गारो-खासी, त्रिपुरा में बांग्ला व ककबरक तथा सिक्किम में अंग्रेजी सहित सिक्किमी, लेपचा, नेपाली, लिबूं, शेर्पा इत्यादि भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। इन राज्यों में कहीं न कहीं स्थानीय भाषाओं को तरजीह दी गई है। इसके विपरीत हिमाचल में हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जबकि हिमाचल में पहाड़ी भाषा का प्रचलन रहा है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ी भारतीय आर्य परिवार भाषा की वह भाषा है, जो वर्तमान में प्रदेश में बोली जाता है। डा. ग्रियर्सन जो एक भाषाविद रहे हैं, उन्होंने भारत की भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए पहाड़ी को भारतीय आर्य भाषा की उप शाखा में रखते हुए, पश्चिमी पहाड़ी की श्रेणी में रखा है। भाषाविदों ने पहाड़ी भाषा की तीन श्रेणियों- पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी व पश्चिमी पहाड़ी में वगीकृत किया है। डा. ग्रियर्सन ने पहाड़ी भाषा किसी विशेष भाषा को नहीं, अपितु भाषाओं के समूह को कहा। भाषायी वर्गीकरण का यह वैज्ञानिक आधार न होकर भौगोलिक है, ऐसा कहना उपयुक्त होगा। ग्रियर्सन द्वारा वर्गीकृत पहाड़ी भाषा में नेपाली भाषा पूर्वी पहाड़ी में आती है, वहीं कुमाऊंनी व गढ़वाली भाषाएं मध्य पहाड़ी भाषा का हिस्सा हैं। पश्चिमी पहाड़ी में हिमाचल प्रदेश में प्रचलित बोलियां आती हैं। पश्चिमी पहाड़ी की बोलियों में कांगड़ी, चंबयाली, मंडयाली, कुल्लवी, लाहौली, किन्नौरी, महासुई, भगाटी, कहलूरी इत्यादि प्रमुख बोलियां रही हैं, जिनको मूलत~ शारदा लिपि में लिखा जाता रहा है। इतना ही नहीं, यहां प्रत्येक क्षेत्र की पृथक बोलियां विद्यमान हैं। इन बोलियों को टांकरी लिपि में लिखने का प्रचलन रहा है। टांकरी लिपि का उद्भव शारदा लिपि से ही हुआ है। बहरहाल, सवाल है कि हिमाचली पहाड़ी भाषा को इसकी लिपि देवनागरी के साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में कब शामिल किया जाएगा?

डा. सतपाल
शिक्षाविद

विधानसभा अध्यक्ष ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरस्कार वितरण समारोह में लिया भाग

देहरादून, संवाददाता। उत्तराखंड 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है, जो राज्य के खेल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस मौके पर उत्तराखंड राइफल संघ द्वारा आयोजित मेडल एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में हुआ। समारोह में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष, ऋतु खण्डूडी भूषण ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने विजेता निशानेबाजों को पदक प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया और इस उपलब्धि के लिए उन्हें बध ई दी। इसके साथ ही, उन्होंने निशानेबाजी और अन्य खेलों के प्रति खिलाड़ियों के समर्पण और मेहनत की सराहना की।

इस अवसर पर ऋतु खण्डूडी भूषण ने कहा, ष्यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन न केवल राज्य की खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा, बल्कि हमारे खिलाड़ियों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी युवा पीढ़ी को खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करें और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करें।

इस कार्यक्रम में प्रमुख निशानेबाजों और अन्य खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान आयोजनकर्ताओं ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से राज्य में खेलों के प्रति जागरूकता और रुचि को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड राइफल संघ के पदाधिकारियों ने आयोजन की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन राज्य में खेलों को नई दिशा और गति देंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो राज्य में खेलों के प्रोत्साहन के साथ-साथ खिलाड़ियों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर प्रदान करेगा।

डीएम व एसएसपी ने किया निरीक्षण

आईएसबीटी पर छोटे हल्के वाहनों के लिए व्यवस्थित कलर कोड पार्किंग तैयार, सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत फ्लाईओवर पर सुरक्षा इंतजाम के साथ यू-टर्न कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण

देहरादून, संवाददाता। डीएम सविन बसंल ने सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत आईएसबीटी पर यातायात व्यवस्था सुचारू करने व छोटे वाहनों हेतु पार्किंग निर्माण कार्य तथा कारगी चौक की तरफ यूटर्न हेतु फ्लाईओवर सुधारीकरण कार्य गतिमान है जिसकी डीएम स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिनका आज डीएम एवं एसएसपी ने निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम एवं एसएसपी के पूर्व में संयुक्त निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी पर यातायात प्लान के सुधारीकरण की दिशा में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में आईएसबीटी पर सुधारीकरण कार्य ध रातल पर उतारे गए हैं। जल्द ही इन सुविध ाओं को जनमानस को विधिवत् समर्पित कर दिया जाएगा।

आईएसबीटी क्षेत्र के बाहर वाहनों द्वारा यात्रियों को बैठाने तथा उतारने से भी यातायात प्रभावित हो रहा था, जिसे अब बंद कर दिया गया है, वाहन में यात्रियों को बैठाने व उतारने हेतु स्थल निर्धारित कर दिया गया है। नियमों का पालन न करने वालों के वाहन सीज किये जा रहे तथा बार-बार ऐसा कृत्य करते पाए जाने पर लाईसेंस निर्लबित की कार्यवाही की जा रही है।

आईएसबीटी फ्लाई ओवर के नीचे जंक्शन प्वांइट पर निरंजनपुर मण्डी की तरफ आने वाले ट्रेफिक प्लान में सुधार करते हुए निरंजनपुर मण्डी से दुपहिया एवं चार पहिया हल्के वाहनों को निरंजनपुर मण्डी की तरफ से फ्लाई आवेर के माध्यम से जंक्शन आईएसलैण्ड से कारगी चौक की तरफ संचालित डायवर्ट कर, आईएसबीटी फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड़ एवं जंक्शन प्वांईट पर यातायात दबाव कम करने का प्रयास किया गया है। वहीं आईएसबीटी प्लाईओवर पर पूर्ण सुरक्षा उपाय करते हुए कारगी की ओर लेफ्टटर्न कर दिया गया है। आईएसबीटी पर 4 पार्किंग कलरकोड में का कार्य पूर्ण हो गया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात मुकेश कुमार, संभागीय परिवहन अधिकारी शैलैष तिवारी, सहायक संभागीय अधिकारी राजेन्द्र विराटिया, अधि.अभि.एनएच कर्णवाल कार्मिक उपस्थित रहे।

भूकंप की अफवाह पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उत्तरकाशी, संवाददाता। भूकंप आने की अफवाह आग की तरह फैल गई। इस कारण नगर क्षेत्र में लोगों ने कड़ाके की ठंड में बुजुर्गों और बच्चों के साथ रात खुले आसमान के नीचे काटी। वहीं इस पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनपद मुख्यालय में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों के बीच किसी शरारती तत्व ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैला दी कि शुक्रवार देर रात को तेज भूकंप आने वाला है। देखते ही देखते यह अफवाह व्हाट्सएप ग्रुपों से लेकर फेसबुक पर वायरल हो गई।

भूकंप के झटकों से दहशत में आए लोग देर रात में अपने बच्चों और बुजुर्गों सहित अन्य लोगों को लेकर खुले आसमान के नीचे सुरक्षित स्थानों पर एकत्रित हो गए। नगर के गंगोरी में खेतों में तो भैरव चौक के लोग अन्नपूर्णा मंदिर और मुख्य बाजार के लोग रामलीला मैदान में एकत्रित हो गए। वहां पर लोगों ने रातभर आग जलाकर रतजगा करने को मजबूर रहे। हालांकि अफवाहों का बाजार गर्म होते ही पुलिस और प्रशासन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसे फर्जी खबर बताते हुए लोगों को सतर्क रहने और भूकंप के तहत जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। लोग सुबह करीब तीन से चार बजे तक खुले आसमान के नीचे रहे। उसके बाद सब लोग अपने घरों को लौट गए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की झूठी अफवाह फैलाने और सामजिक सौहार्द को बिगाड़ने को लेकर उपद्रव आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसपी सरिता डोबाल ने शहरवासियों से झूठी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी सूचना के लिए प्रशासन की वेबसाइट और सोशल हैंडल से जानकारी लें।

रा.इं.का. चोपता में पुलिस बल ने चलाया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

रुद्रप्रयाग, संवाददाता। 35वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस बल ने राइका चोपता में छात्र-छात्राओं को यातयात नियमों एवं साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया। साथ ही नशा उन्मूलन को लेकर भी छात्रों को जागरूक किया। एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे के निर्देशन में आम-जनमानस व स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक किया जा रहा है। चौकी प्रभारी दुर्गाधार कुलेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में राइका चोपता में छात्र-छात्राओं, अध्यापकों व कर्मचारी को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों व प्रावधानों, साइबर क्राइम के नए तौर तरीकों तथा साइबर क्राइम से बचाव के लिए दैनिक जीवन में बरती जा सकने वाली आवश्यक सतर्कता से अवगत कराया। समाज के सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखने के लिए महिला सुरक्षा एवं नशा उन्मूलन की आवश्यकता के संदर्भ में भी भली भांति जानकारी दी।

संक्षिप्त समाचार...

3 फरवरी को शुरू होगा पल्स अनीमिया महाअभियान

रुद्रप्रयाग, संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में 3 फरवरी से शुरू होने वाले पल्स अनीमिया महा अभियान की तैयारियां पूरी हो गई है। अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की अनीमिया जांच के लिए जनपद में 81 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में जांच केंद्र व 13 चिकित्सा इकाईयों में अनीमिया उपचार केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राम प्रकाश ने बताया कि गर्भवस्था में अनीमिया अथवा खून की कमी से मां के स्वास्थ्य में असर डालने के साथ-साथ शिशु स्वास्थ्य की जटिलताओं का कारण भी बन सकता है, जिसके दृष्टिगत 3 फरवरी से 10 फरवरी तक पल्स अनीमिया महा अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पल्स अनीमिया महाअभियान के तहत जनपद में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है वहीं, अन्य तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी 81 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को इस अभियान के अंतर्गत जांच केंद्र बनाया गया है, जहां गर्भवती महिलाओं के हीमोग्लोबिन की नि:शुल्क जांच करने के साथ-साथ अनीमिया से बचाव के बारे में जरूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। बताया कि जांच में हीमोग्लोबिन कम होने पर संबंधित गर्भवती महिला चिकित्सकों की देखरेख में आयरन सूक्रोज की दवा दी जाएगी। जिसके लिए 13 उपचार केंद्र जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग, सीएचसी अगस्त्यमुनि, पीएचसी दुर्गाधार, खेड़ाखाल, चंद्रनगर, भीरी, सीएचसी जखोली, पीएचसी घेंघड़खाल, रणधार, बैनोली, पीएचसी ऊखीमठ, फाटा व गुप्तकाशी में उपचार केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने जनपद की समस्त गर्भवती महिलाओं को 3 फरवरी को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर हीमोग्लोबिन की जांच करवाने की अपील की है। वहीं, उक्त अभियान के तहत शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में स्त्री रोग विषेशज्ञ डॉ सोनालिनी द्वारा चिकित्सकों व एएनएम को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस अवसर डॉ मोनिका, डीडीएम अशोक नौटियाल, काउंसलर आरकेएसके विपिन सेमवाल आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने खो-खो में दोनों वर्गों में जीता स्वर्ण पदक

देहरादून, संवाददाता। 38वें राष्ट्रीय खेल के पांचवें दिन खो-खो प्रतियोगिता में महाराष्ट्र ने अपना दबदबा कायम रखते हुए पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। पुरुष वर्ग के फाइनल में महाराष्ट्र ने ओडिशा को 32-26 के स्कोर से हराया, वहीं महिला वर्ग में भी महाराष्ट्र ने ओडिशा को 31-28 से मात दी। गौरतलब है कि 37वें राष्ट्रीय खेल में भी खो-खो के पुरुष और महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले महाराष्ट्र और ओडिशा के बीच ही खेले गए थे। पुरुषों की कांस्य पदक प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल और केरल के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। दोनों टीमों ने एक ही समय पर खेल समाप्त किया, जिसके चलते मुकाबला सडन डेथ में गया और दोनों टीमों को संयुक्त रूप से कांस्य पदक प्रदान किया गया। महिला वर्ग के कांस्य पदक मैच में दिल्ली और कर्नाटक के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। यह मैच भी सडन डेथ में पहुंचा और अंतत: दोनों टीमों को संयुक्त रूप से कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेल में खो-खो प्रतियोगिता का यह रोमांचक समापन खेल प्रेमियों के लिए यादगार बन गया।

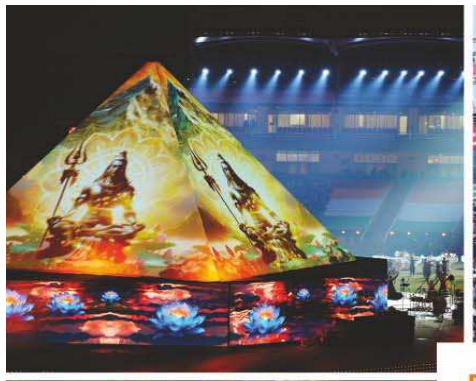

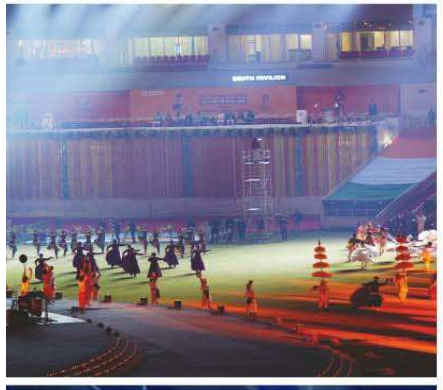

उत्तराखण्ड शासन
देवभूमि रजत उत्सव
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS
सत्यमेव जयते
UTTARAKHAND
INDIA
38वें राष्ट्रीय खेल
उत्तराखंड
रजत जयंती वर्ष
28 जनवरी - 14 फरवरी 2025
संकल्प से शिखर तक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है, जिस प्रकार जी20 का सफल आयोजन प्रदेश ने किया था उसी के ही अनुरूप राष्ट्रीय खेल भी ऐतिहासिक होगा।
पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हरसंभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक है।
नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री
38वें राष्ट्रीय खेलों के
उद्घाटन समारोह में पधारने पर

मा. प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी जी
का
हार्दिक आभार!
देवभूमि बनी ख़ेलभूमि
• देहरादून, ऋषिकेश टिहरी, ऊधमसिंह नगर, हल्द्वानी, हरिद्वार, नई टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन
• देशभर के लगभग 10,000 खिलाड़ी कर रहे हैं प्रतिभाग
• 35 खेलों में प्रतियोगिताएं
• उत्तराखण्ड के लिए खेलों की मेजबानी का ऐतिहासिक अवसर
• युवाओं को प्रेरित करने के लिए खेल संस्कृति को बढ़ावा
• उत्तराखण्ड के खेल परिदृश्य के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर
अधिक जानकारी के लिए लॉगइन करें
www.38nguk.in
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी।
www.uttarainformation.gov.in | uttarakhandDIPR | DIPR_UK | uttarakhand DIPR
Uttarakhand

खिलाड़ियों के लिए सरकार ने तिजोरी से निकाले 3794 करोड़ रुपए

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2025-26 सत्र के लिए आम बजट पेश किया। इस दौरान खेल बजट भी आया। पिछली बार की तुलना में इस बार खेल बजट में करीब 392 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं, सरकार की प्रमुख परियोजना खेलो इंडिया को एक बार फिर फायदा हुआ और जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने वाले इस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय बजट में सबसे अधिक राशि आबंटित की गई है। अगले साल राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों का आयोजन होना है। ऐसे में खेल मंत्रालय के बजट में पिछले साल की तुलना में करीब 352 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इस बार खेल बजट 3794.30 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछली बार 3,442.32 करोड़ रुपए का था। खेल मंत्रालय के लिए उससे पहले के वित्तीय वर्ष के लिए बजट 3,396.96 करोड़ रुपए था। खेलो इंडिया युवा खेलों 2018 की शुरुआत के बाद से सरकार ने इसमें और खेल आयोजनों को जोडऩा जारी रखा है। मंत्रालय ने उसी वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेल और 2023 में खेलो इंडिया पैरा खेलों शुरू करने के साथ 2020 में खेलो इंडिया

विश्वविद्यालय खेलों की शुरुआत की। देश भर में सैकड़ों खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रतिभाशाली उदीयमान खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करना है। खेलो इंडिया के कई एथलीट ओलंपिक दल में भी शामिल होते हैं। धिनिधि देसिंघु इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं।

खेलो इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा

खेल मंत्रालय के इस बजट में से खेलो इंडिया के लिए 1000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। पिछले बजट (2024-25) में से खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। यह रकम 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान 880 करोड़ रुपए के संशोधित आबंटन से 20 करोड़ रुपए अधिक थी। 2024-25 की तुलना में अब 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए खेलो इंडिया को आबंटित रकम में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में खेलो इंडिया में भारी निवेश किया है, क्योंकि यह कार्यक्रम देश के सभी हिस्सों से प्रतिभाओं को सामने लाने का काम करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में खेलो इंडिया का वास्तविक आबंटन 596.39 करोड़ रुपए था। 2023-24 के बजट में लगभग 400 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाकर 1,000 करोड़ कर दिया गया था। बाद में इसे हालांकि संशोधित कर 880 करोड़ किया गया था।

ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी

राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता के लिए निर्धारित राशि को भी 340 करोड़ रुपए से मामूली तौर पर बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारत वर्तमान में 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए एक महत्त्वाकांक्षी बोली की तैयारी कर रहा है। भारत ने इसके लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को एक आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

विराट की सिक्योरिटी में बड़ी चूक; मैदान में घुसे तीन शख्स, स्टेडियम में अफरा-तफरी का आलम

नई दिल्ली, एजेंसी। फैंस के लिए अपने क्रिकेट हीरोज से मिलने के लिए सिक्योरिटी तोडक़र मैदान में घुसना आम बात है, लेकिन ऐसा अकसर इंटरनेशनल मैच में होता है। मगर अरुण जेटली स्टेडियम में बीते तीन दिन के भीतर दो मर्तबा ऐसा नजारा देखने को मिला। मौका दिल्ली और रेलवे के बीच खेले गए एलीट ग्रुप डी के मुकाबले का था। रणजी ट्रॉफी में खेलने आए विराट कोहली से मिलने के लिए उनके फैंस ने सारी हदें पार कर दी। शनिवार को तीन फैंस 20 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर मैदान में घुसने में कामयाब रहे। इन तीनों फैंस को हालांकि तुरंत ही पकड़ लिया गया और वह कोहली के करीब नहीं जा पाए। यह घटना लंच से ठीक पहले घटी जब कोहली कवर पर क्षेत्ररक्षण कर रहे थे।

एक पारी और 19 रन से जीती दिल्ली

मैच में टॉस जीतकर मेजबान दिल्ली ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बैटिंग का बुलावा मिलने पर रेलवे की टीम पहली पारी में सिर्फ 241 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में दिल्ली ने आयुष बदोनी और सुमित माथुर के शानदार अर्द्धशतकों की मदद से 374 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। इस तरह रेलवे पहली पारी के आधार पर दिल्ली से 133 रन पिछड़ गई। मगर रेलवे दूसरी पारी में सिर्फ 114 रन पर ही सिमट गई। इस तरह पारी और 19 रन से दिल्ली ने मैच अपने नाम किया।

मुंबई ने हराया मेघालय

नई दिल्ली। शार्दुल ठाकुर और तनुष कोटियान की दमदार गेंदबाजी की बदौलत मुंबई की टीम शनिवार को मेघालय को पारी और 456 रन से रौंदकर रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। शार्दुल और तनुष दोनों ने चार-चार विकेट अपने नाम किए।

व्यापार.....

केंद्रीय बजट 2025-लोगों, इनोवेशन और ग्रामीण समृद्धि में निवेश

देहरादून। केंद्रीय बजट 2025 एक परिवर्तनकारी एजेंडे की रूपरेखा तैयार करता है जो हमारी अर्थव्यवस्था की तत्काल जरूरतों को पूरा करता है और साथ ही एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। यह बजट भारत के आम आदमी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक नागरिक तेजी से विकसित हो रहे लैंडस्केप में फल-फूल सके। इस बजट के लिए सरकार की रणनीतिक योजना हमारे समाज के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ को दर्शाती है। बजट 2025 में प्रस्तावित डेवलपमेंट मेजर एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट को सक्षम करने, लोगों, अर्थव्यवस्था और इनोवेशन में निवेश करने और समावेशी विकास योजना पर सभी को एक साथ लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक क्षेत्रों पर केन्द्रित हैं।

बजट के बारे में चर्चा करते हुए, भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयन्त चौधरी ने कहा, केंद्रीय बजट 2025 एक दूरदर्शी विज़न को दर्शाता है जो न केवल कर सुधारों के माध्यम से आर्थिक विकास को मजबूत करता है बल्कि भारत के भविष्य को चलाने वाले प्रमुख क्षेत्रों को भी प्राथमिकता देता है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने और कपास उत्पादकता को बढ़ावा देने से लेकर क्रेडिट गारंटी के माध्यम से स्टार्टअप और एमएसएमई को सशक्त बनाने तक, ये उपाय उद्यमिता और ग्रामीण समृद्धि को गति देंगे। गहन तकनीकी फंडिंग, एआई-संचालित शिक्षा और कौशल में 5 सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस पर ध्यान भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, जिला अस्पतालों में कैंसर देखभाल को मजबूत करना और गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना समावेशी विकास के लिए एक संतुलित अप्रोच प्रदर्शित करता है। यह बजट अधिक कुशल, लचीले और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। सरकार वंचित समुदायों के उत्थान, महिलाओं को सशक्त बनाने और हमारे किसानों का सहयोग करने वाले लक्षित उपायों के साथ समावेशी विकास को प्राथमिकता दे रही है। यह व्यक्तिगत करदाताओं के लिए भी एक बड़ी जीत है क्योंकि वे अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए, सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट देकर मध्यम वर्ग को राहत दी है।

देवेन्द्र फडणवीस ने स्किल इंडिया डिजिटल हब के मराठी संस्करण का अनावरण किया

देहरादून। महाराष्ट्र में एक समावेशी और मजबूत स्किलिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में विश्व मराठी सम्मेलन 2025 के अवसर पर मराठी भाषा में स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) प्लेटफॉर्म का अनावरण किया।

फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ सिद्ध का मराठी संस्करण लॉन्च किया, जो प्रोफेशनल, छात्रों और शोधकर्ताओं को वैल्यूबल कंटेंट के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में सक्षम बनाएगा, जिससे पूरे महाराष्ट्र में व्यापक ज्ञान प्रसार सुनिश्चित होगा।

भाषा की बाधाओं को तोड़कर, यह पहल भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देती है और नागरिकों को उनकी मातृभाषा में आवश्यक जानकारी प्रदान करके सशक्त बनाती है, जैसा कि एनईपी 2020 में कल्पना की गई है। यह प्लेटफॉर्म युवाओं को 7000 से अधिक कौशल पाठ्यक्रमों में खुद को कुशल बनाने में सहायता करेगा जिसमें उद्योग 4.0 पाठ्यक्रम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कुछ नाम शामिल हैं।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के मराठी भाषा मंत्री श्री उदय सामंत, लोकसभा सदस्य श्रीरंग बारणे, महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य नीलम गोरे, महाराष्ट्र विधान सभा सदस्य सिद्धार्थ शिरोले, विधान सभा सदस्य बापूसाहेब पठारे, एनएसडीसी के सीईओ एवं एनएसडीसी इंटरनेशनल के एमडी वेद मणि तिवारी तथा विभिन्न क्षेत्रों के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। एनएसडीसी के सीईओ वेद मणि तिवारी को मंत्री उदय सामंत द्वारा सम्मानित किया गया, जिन्होंने सिद्ध को ज्ञान सुलभता में बदलाव लाने वाली एक अग्रणी पहल के रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तिवारी इनोवेशन को बढ़ावा देने, शिक्षा के साथ टेक्नोलॉजी को एकीकृत करने और यह सुनिश्चित करने में सबसे आगे रहे

हैं कि कौशल विकास देश के हर कोने तक पहुंचे। उनके अथक प्रयासों ने सिद्ध को भाषाई समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित किया है।

समारोह में बोलते हुए और कौशल और डिजिटल सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, तिवारी ने कहा कि सिद्ध ने एक साल से अधिक समय में राष्ट्रीय स्तर पर 1.26 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन दर्ज किए हैं। यह हजारों कौशल पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहा है, और मराठी संस्करण के अनावरण के साथ, एनएसडीसी लाखों मराठी भाषी युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें अपने करियर की संभावनाओं को अनलॉक करने में मदद करने के लिए प्लेटफॉर्म की उपयोगिता का प्रदर्शन कर रहा है। रजिस्ट्रेशन के मामले में, महाराष्ट्र देश के शीर्ष पांच राज्यों में से एक है, जबकि यूजर ट्रैफिक के मामले में, राष्ट्रीय स्तर पर 30 प्रतिशत के साथ, यह उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। मराठी संस्करण के अनावरण के साथ, कौशल पाठ्यक्रमों और प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता और रजिस्ट्रेशन में और वृद्धि होगी। मराठी उन 23 भाषाओं में से एक है जिसमें इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा जा सकता है।

एचडीएफसी बैंक की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता की केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया

देहरादून। मध्यम वर्ग की ओर से मांग में कमी की चिंताओं को संबोधित करते हुए, बजट में व्यक्तिगत आयकर स्लैब को तर्कसंगत बनाया गया है, साथ ही स्रोत पर कर कटौती की सीमा में संशोधन किया गया है। इससे मध्यम वर्ग द्वारा उपभोक्ता मांग और बचत को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिसने उच्च मुद्रास्फीति और कम आय वृद्धि से चुनौतियों का सामना किया है। आम आदमी के लिए रियायतों से परे, बजट लाईट टच नियामक दृष्टिकोण के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। अगले पांच साल की राजकोषीय रणनीति कृषि, एमएसएमई, निर्यात को बढ़ावा देने और भारत की क्षमता निर्माण में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में तैयार की गई है। वित्त मंत्री की राजकोषीय रणनीति खपत को बढ़ावा देने की ओर झुकी हुई है, जबकि पूंजीगत व्यय लक्ष्य को 2024-25 की बजट योजनाओं से मोटे तौर पर अपरिवर्तित रखा गया है। बजट द्वारा प्रदान किया गया श्काउंटर साइक्लिकल पुशश् राजकोषीय समेकन की अपनी व्यापक रणनीति के भीतर है, जो 2025-26 में 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे को लक्षित करता है। आयकर में बदलाव के कारण राजस्व में कमी के बावजूद, 2025-26 में व्यय पक्ष पर दबाव के माध्यम से राजकोषीय समेकन प्राप्त किया गया है। आज की बजट घोषणा 2025-26 में जीडीपी वृद्धि के 6.6 प्रतिशत की हमारी उम्मीद को पुख्ता करती है। बॉन्ड मार्केट के लिए कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है क्योंकि बाजार उधारी मोटे तौर पर उम्मीदों के अनुरूप है। आगामी दरों में कटौती और आरबीआई द्वारा खुले बाजार में खरीद के साथ बॉन्ड यील्ड में गिरावट की उम्मीद है।

पल्टन बाजार में सीसीटीवी, पीए सिस्टम का विधिवत् शुभारम्भ

■आईएसबीटी सुधारीकरण का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण ■पुलिस के 207 कैमरे कन्ट्रोलरूम से इन्टिग्रेट जल्द ■डीएम ने एसएसपी से मांगे 10 पिंक बूथ के प्रस्ताव ■11 नई यातायात लाइट को डीएम ने दी धनराशि

देहरादून, संवाददाता। जनमानस की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पल्टन बाजार में स्थापित किये गए 22 सीसीटीवी कैमरे एवं पीए सिस्टम का डीएम सविन बसंल एवं एसएसपी अजय सिंह ने आज कोतवाली देहरादून से विधिवत् शुभारंभ कर दिया है। जिलाधिकारी सविन बसंल ने कहा कि जो भी हमारे संसाधन है वह जनमानस/सार्वजनिक हित के लिए है। सरकार की सभी सेवाओं एवं सामजिक योजना जिनपर सरकार व्यय कर रही है इन सभी सुविधाओं का उद्देश्य है अन्तिम छोर के व्यक्ति को लाभ मिले। इसके लिए निरंतर प्रयासरत् है। उन्होंने कहा कि जनहित जो भी सुझाव मिलेंगे उन पर विचार किया जाएगा।

जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संयुक्त भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पल्टन बाजार में जनमानस, व्यापारियों, महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पिंक बूथ बनाने के निर्देश दिए गए थे जिसके लिए जिलाधिकारी ने पुलिस को धनराशि निर्गत की थी इसी का परिणाम है कि आज पल्टन बाजार में सीसीटीवी एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम का विधिवत् शुभारंभ किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिलाधिकारी को शहर में सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था हेतु प्रस्ताव जा रहे उसे तत्वरित स्वीकार करते हुए धनराशि निर्गत की जा रही है, जिससे शहर में कानून व्यवस्था अन्य व्यवस्था बनाने में सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास बजट लिमिटेशन होती है, किन्तु जिला प्रशासन के सहयोग से अब यह लिमिटेशन खत्म हो रही है जल्द ही शहर में और अधिक अच्छी व्यवस्था बनाई जा सकेगी। उन्होंने कहा जल्द ही ऋषिकेश में भी 46 कैमरे स्थापित किये जाएंगे।

इस अवसर पर उपस्थित व्यापार मण्डल के सदस्यों से जिलाधिकारी एवं एसएसपी की कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि डीएम व एसएसपी के समन्वय से जो जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत कार्य किये जा रहे हैं वह सराहनीय है तथा यह जिला प्रशासन एवं पुलिस का सबसे अच्छा समन्वय है, जिससे जनहित में अच्छे कार्य हो रहे हैं।

वहीं व्यापारियों द्वारा सर्राफा बाजार में कैमरे लगाने की मांग की गई जिस पर जिलाधिकारी ने पुलिस को प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात मुकेश कुमार, व्यापारी संगन से संतोष सिंह नागपाल, सुनील मेसोन, पंकज मैसोन सहित व्यापार संगठनों के पदाधिकारी, व्यापारी एवं जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहे।

देशभर के खिलाड़ी देखें अल्मोड़ा की संस्कृति : रेखा आर्या

अल्मोड़ा, संवाददाता। खेल मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कहा कि देशभर से आए खिलाड़ियों को अल्मोड़ा की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों से जरूर परिचित कराया जाए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यहां का प्रसिद्ध मंदिर जागेश्वर धाम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, सभी खिलाड़ियों को वहां जाना चाहिए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हर दिन किसी न किसी टीम को अधिकारी इस मंदिर के दर्शन कराएं। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों से गोल्ज्यू देवता के मंदिर के दर्शन करने की अपील भी की। खेल मंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा में योगासन की प्रतियोगिता होना सांस्कृतिक नगरी के लिए गौरव की बात है। खेल मंत्री का कहना था कि उत्तराखंड योगासन की जन्म भूमि है इसलिए हम अपने प्रदेश की टीम से योगासन में कुछ अतिरिक्त अपेक्षाएं रखते हैं।खेल मंत्री ने बहुत कम समय के नोटिस पर योगासन का शानदार आयोजन करने के लिए जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे की पीठ थपथपाई।

योगासन प्रतियोगिता 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता पांच श्रेणियों में आयोजित की जाएगी जिसमें ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप शामिल हैं। इन सभी श्रेणियों में कुल 66 पदक दिए जाएंगे, जिसमें 22 स्वर्ण, 22 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। इस अवसर पर विधायक मनोज तिवारी, मेयर अजय वर्मा, रघुनाथ सिंह चौहान,भाजपा,जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा,महामंत्री धर्मेंद्र बिष्ट, पूर्व जिला अध्यक्ष रवि रौतेला, गणेश जलाल, अशोक जलाल, ललित तिवारी, आदि मौजूद रहे।

उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही ऊर्जा डिमांड

प्रदेश में सालों से लटके है कई पावर प्रोजेक्ट
सरकार की 21 परियोजनाओं पर टिकी लोगों की आस
विद्युत की डिमांड पीक सीजन में 2600 मेगावाट प्रतिदिन तक पहुंची

देहरादून, संवाददाता। आपदाओं से जुड़ी आशंकाओं के बीच प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हमेशा राज्य के लिए दूभर रहा है। शायद यही कारण है कि राज्य की सबसे बड़ी ताकत माना जाने वाला एनर्जी सेक्टर आज राजकोष पर भारी पड़ रहा है। स्थिति ये है कि उत्तराखंड में विद्युत डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस समस्या का समाधान करने वाली जल विद्युत परियोजनाएं पिछले एक दशक से न्यायिक प्रक्रिया में फंसी हुई हैं।

उत्तराखंड के पास ऊर्जा संकट से उबरने का एकमात्र रास्ता जल विद्युत परियोजनाएं हैं। लेकिन पिछले एक दशक से जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर चल रही लड़ाई अब भी जारी है। कानूनी नूरा कुश्ती के बीच उत्तराखंड के लिए मुसीबत ये है कि एक तरफ राज्य को प्राकृतिक खतरों से निपटना है, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक संपदा का संतुलित दोहन कर जरूरतों को भी पूरा करना है। लेकिन एनर्जी सेक्टर में कानूनी दांव पेंच के कारण राज्य ऐसा नहीं कर पा रहा है। फिलहाल, उत्तराखंड सरकार की नजर उन 21 परियोजनाओं पर है, जिन्हें मंजूरी मिलती है तो प्रदेश काफी हद तक अपनी विद्युत की डिमांड को पूरा कर सकता है।

फिलहाल विद्युत आपूर्ति पूरी कर पाना सरकार के लिए आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि राज्य में लगातार विद्युत की डिमांड बढ़ती जा रही है। जबकि उस लिहाज से उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। प्रदेश में विद्युत की डिमांड पीक सीजन में 2600 मेगावाट प्रतिदिन तक पहुंची है। जबकि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का सर्वाधिक उत्पादन 900 मेगावाट से 1000 मेगावाट तक का ही है। इस तरह 1600 मेगावाट से ज्यादा की बिजली केंद्रीय पूल या खुले बाजार से खरीदकर राज्य को मिलती है। सामान्य तौर पर बिजली की डिमांड करीब 2 हजार से 2100 मेगावाट तक होती है। ऐसे ही उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड समानता पर 300 से 400 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है।

उत्तराखंड में लगातार बिजली की डिमांड बढ़ रही है। इसे प्रतिवर्ष के तौर पर करीब 3.7 से 5.5 फीसदी तक बढ़ोत्तरी के रूप में देखा जा रहा है। जबकि हर साल उत्तराखंड तकरीबन 1000 करोड़ की बिजली खरीद रहा है। जिससे उत्तराखंड के राजकोष पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। उत्तराखंड में तमाम नदियों की मौजूदगी के चलते राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन की क्षमता रखता है। यानी तकरीबन 20 हजार मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन राज्य में हो सकता है। लेकिन अभी प्रदेश में 4249 मेगावाट की क्षमता वाले प्रोजेक्ट ही लगाए गए हैं।

उत्तराखंड सरकार राज्य में उन 21 परियोजनाओं को शुरू करने की मंजूरी चाहती है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीसरी कमेटी ने हरी झंडी दी थी। हालांकि केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय को इन परियोजनाओं पर घोर आपत्ति है। दरअसल, केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जल विद्युत परियोजनाओं पर स्वतरू संज्ञान लेते हुए गंगा और सहायक नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने पर रोक लगाई थी।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में पर्यावरणविद् रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर प्रस्तावित 24 परियोजनाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में परियोजनाओं को आगे न बढ़ाने की सिफारिश की थी।

लंबित जनगणना के लिए आवंटित किए गए मात्र 574 करोड़

नई दिल्ली, संवाददाता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025-26 के लिए आम बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कई अहम एलान किए। वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा देते हुए 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का एलान किया है। वहीं, अगर बजट में किए गए प्रावधानों को देखें तो इस बार भी जनगणना होने की संभावना नहीं दिख रही है। इस बार बजट में जनगणना के लिए 574.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी/भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) के लिए 574.80 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं, 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में इस बाबत 3,768

करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसको देखते हुए कहा जा रहा है कि ये एक संकेत है कि करीब पांच साल की देरी के बाद भी जनगणना नहीं कराई जा सकती।

बता दें कि बजट 2024-25 के अनुसार, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी के लिए 1,309.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 2023-24 में यह 578.29 रुपये था। वहीं, 24 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8754.23 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2021 आयोजित करने और 3,941.35 करोड़ रुपये [...] राष्ट्रीय जनसंख्या र[...] (एनपीआर) को अपडेट क[...] के प्रस्ताव को मंजूरी दी ग[...] थी।

अधिकारियों का दावा [...] है कि लंबित जनगणना [...] कराने और एनपीआर [...] अपडेट कराने के लिए सरकार को करीब-करीब 12000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। गौरतलब है कि जनगणना और एनपीआर को अपडेट करने का काम 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक देश भर में किया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण तब इसे स्थगित कर दिया गया था। फिलहाल अभी तक जनगणना का काम रुका हुआ है। सरकार ने अभी तक नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। बता दें कि [...]ाना कराई जाएगी [...] डिजिटल जनगणना [...]एनपीआर को उन [...]लिए अनिवार्य बना [...] दिया गया है जो [...] सरकारी अधि[...]कारियों के बजाय [...] स्वयं जनगणना फॉर्म भरने के अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्व-गणना पोर्टल डिजाइन किया है जिसे अभी लॉन्च किया जाना बाकी है।

जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति बनाने और उन पर अमल करने के साथ-साथ देश के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम होते हैं। इससे न सिर्फ जनसंख्या बल्कि जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति कई अहम पहलुओं का पता चलता है। हालांकि, इस बार की जनगणना के आंकड़े लोकसभा सीटों के परिसीमन और संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने संबंधी प्रावधानों के कारण बेहद अहम हैं। भारत में हर दस साल में जनगणना होती है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1947 में आजादी मिलने के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी और आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी।

चैंपियन-उमेश कुमार विवाद में राकेश टिकैत की एंट्री

पुलिस में मचा हड़कंप, आनन-फानन में लिया एक्शन

रुड़की, संवाददाता। हरिद्वार के रुड़की में खानपुर विधायक उमेश कुमार के आवास पर राकेश टिकैत के आने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे। विधायक के आवास पर चारों तरफ बेरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया गया। दरअसल, राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर दोनों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने की पेशकश की थी।

बताते चलें खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चौंपियन के बीच विवाद के मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। जिसमें उम्होंने दोनों के बीच सुलह कराने की पेशकश की थी। इसी के चलते ही शनिवार दोपहर को राकेश टिकैत के पहले मंगलौर गुड मंडी और वहां से विधायक उमेश कुमार के कैम्प कार्यालय पर आने की जानकारी पुलिस को मिल गई। इस सूचना से पुलिस महकमें में हड़कम्प मच गया।

जिसके बाद आनन-फानन में सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र बिष्ट, गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऐश्वर्य पाल पुलिस टीम के साथ खानपुर विधायक उमेश कुमार के कैम्प कार्यालय पहुंचे। पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया। हालांकि, राकेश टिकैत वहां नहीं पहुंचे। जानकारी मिली है कि राकेश टिकैत हरिद्वार में डाम कोठी गए हैं। फिलहाल पुलिस ने खानपुर विधायक उमेश कुमार के कैम्प कार्यालय पर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की हुई है। जिससे कोई भी अज्ञात व्यक्ति वहां से न निकल सके।

देहरादून साइक्लिंग क्लब छात्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में कर रहा सहयोग

देहरादून, संवाददाता। देहरादून साइक्लिंग क्लब ने शहर के विभिन्न स्कूलों के साथ मिलकर छात्रों के बीच मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने की एक अनूठी पहल की है। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों को यह समझाना है कि पढ़ाई के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है।

आज के दौर में मोटापा, अधिक वजन, मधुमेह (शुगर), उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन), आंखों का रोग, जैसी बीमारियाँ छात्रों के बीच तेजी से बढ़ रही हैं। इसके पीछे मुख्य कारण असंतुलित दिनचर्या, शारीरिक गतिविधियों की कमी और खानपान की गलत आदतें हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए देहरादून साइक्लिंग क्लब छात्रों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्कूलों का दौरा कर रहा है। कल, 2 फरवरी 2025 को, क्लब की टीम श्री राम सेंटेनियल स्कूल का दौरा करेगी, जहाँ स्कूल के प्रधानाचार्य श्री अरविंद कुमार से मुलाकात की जाएगी। इस दौरान छात्रों को साइक्लिंग और अन्य शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में बताया जाएगा और उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि वे अपने दैनिक जीवन में खेल-कूद और व्यायाम को शामिल करें। देहरादून साइक्लिंग क्लब का मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए, यह अभियान छात्रों के लिए न केवल जागरूकता का माध्यम बनेगा बल्कि उन्हें अपने स्वास्थ्य और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा।

केंद्रीय बजट उत्तराखंड के लिए काफी मददगार साबित होगा: सतीश

देहरादून, संवाददाता। भारतीय व्यापार मंडल देहरादून के अध्यक्ष सतीश अग्रवाल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 उत्तराखंड के लिए काफी लाभदायक होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया गया है यह वाकई में प्रदेश हित में कार्य करेगा। हमारा उत्तराखंड प्रदेश एक पर्यटक प्रधान प्रदेश है एवं यहां पर देश विदेश से काफी टूरिस्ट आते हैं और यहां के अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाते हैं। इस बजट में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने की बात कही गई है जो हमारे प्रदेश के लिए काफी फायदेमंद होगी। वही इस बजट से उत्तराखंड के लघु एवं मध्यम स्तर के व्यापारियों के लिए भी काफी कुछ सहूलियत देने वाला है। बजट 2025-26 मध्यम वर्ग के लोगों के लिए काफी राहत देने वाला बजट है। 12 लाख तक की आय को कर मुक्त का जो प्रावधान पेश किया गया है वह नौकरी-पेशा वाले लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। आम जनता के लिए भी यह काफी किफायती बजट है जिसके अंतर्गत एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, एविएशन, टेक्सटाइल एवं इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों में राहत दी गई है इससे आम आदमी के बचत में इजाफा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

उत्तराखंड के मास्टर्स एथलीटों का कुन्नमकुलम केरल में शानदार प्रदर्शन लगातार जारी

देहरादून, संवाददाता। छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट का कुन्नमकुलम केरल में 31 जनवरी से 3 फरवरी तक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें पूरे देश से 22 राज्यों के 35 वर्ष से 85 साल से अधिक तक के लगभग 1500 मास्टर्स पुरुष और महिला खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। आज की प्रतियोगिता में देवभूमि मास्टर्स एथलेटिक एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन के 45 सदस्य दल ने 11 गोल्ड, 5 सिल्वर एवं 03 कांस्य पदक प्राप्त किए। विभिन्न आयु वर्ग में सुमित शाह, घनानंद पांडे, घनश्याम पांडे, सतीश चंद चौहान, ललित चन्द्र जोशी, राजेंद्र प्रसाद जोशी, दीपक नेगी, भावना गढ़िया, मीना कंडारी, नीमा बिष्ट, स्वाति पोखरियाल, माला शर्मा ने स्वर्ण पदक तथा सिल्वर पदक प्राप्त करने वालों में दीपक नेगी जी0एन0 पंत, यशोदा कांडपाल, सबल सिंह बिष्ट तथा कांस्य पदक अर्चना बिष्ट, घनानंद पांडेय, सुभाष चंद्र भट्ट ने प्राप्त कर उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन किया।

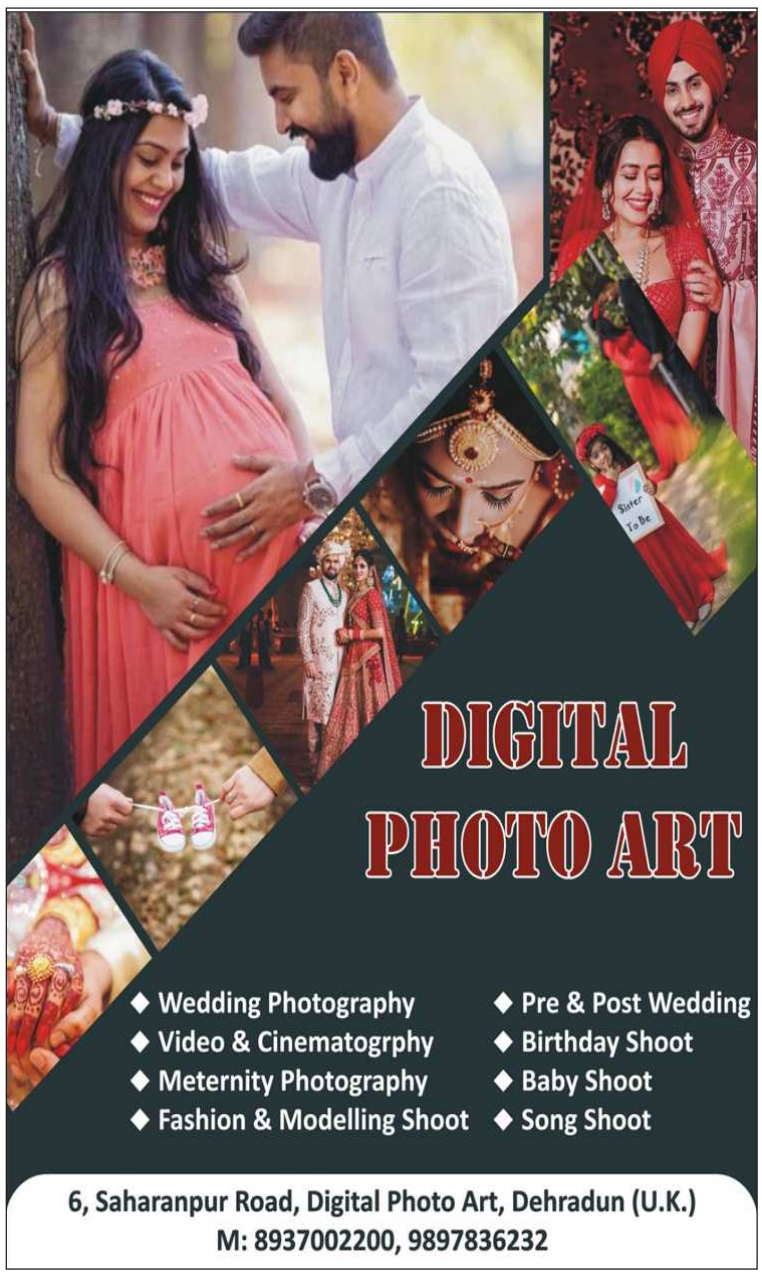

देसी अंदाज में काम की बात कह गए सुजीत मान

-मौली संवाद कॉन्क्लेव: सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए न्यूट्रिशन की अहमियत पर चर्चा -पूर्व में अर्जुन व द्रोणाचार्य पुरस्कार जीत चुके हैं सुजीत -राष्ट्रीय खेलों में कॉन्क्लेव की सीरीज, रोज हो रहे सत्र

देहरादून, संवाददाता। रेसलिंग की दुनिया में सुजीत मान का जाना पहचाना नाम रहा है। फिर चाहे एक खिलाड़ी की भूमिका रही हो या अब कोच की भूमिका। दोनों क्षेत्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके खाते में हैं। यानी वह अर्जुन व द्रोणाचार्य दोनों पुरस्कार जीत चुके हैं। शनिवार को वह राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित मौली संवाद कॉन्क्लेव में शामिल हुए। देसी अंदाज में उन्होंने कई काम की बातें खिलाड़ियों और छात्रों से साझा कीं।

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित कॉन्क्लेव में सुजीत मान ने खेलों में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए न्यूट्रिशन की अहमियत को बेहद सरल शब्दों में समझाया। इस क्रम में फिल्म दंगल का जिक्र आया, तो विनेश फोगाट के ओलंपिक में स्वर्ण पदक से चूक जाने का भी।

कॉन्क्लेव का विषय था-एडवांस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन फॉर पीक परफॉर्मेंस। विषय से जुड़े तकनीकी पक्षों को सामने रखने में डा कोमी कल्पना का अनुभव भी सत्र में दिखाई दिया। उन्होंने न्यूट्रिशन लेने के अलावा रोजाना तीन लीटर पानी अनिवार्य रूप से पीने पर जोर दिया। संचालन करते हुए पीईएफआई के सचिव डॉ पीयूष जैन ने भी कई अहम बातें कीं। राष्ट्रीय खेलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सिन्हा ने भी न्यूट्रिशन पर चर्चा की।

कॉन्क्लेव में तीन फरवरी को द साइंस ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग और एंडी डोपिंग अवेयरनेस विषय पर सत्र होंगे। हमने कभी नहीं जाना मोमो, गोलगप्पे क्या हैं: पूर्व रेसलर सुजीत मान ने खिलाड़ियों और छात्रों को न्यूट्रिशन फूड ही लेने की सलाह देते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं जाना कि मोमो, गोलगप्पे क्या है।

38वें राष्ट्रीय खेल के नए इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्षा जल संचयन की विशेष व्यवस्था

देहरादून, संवाददाता। 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन हेतु बनाए गए सभी नए इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग) की विशेष व्यवस्था की गई है। यह कदम जल संरक्षण को बढ़ावा देने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय खेल के आयोजन स्थल पर बनाए गए स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य सुविधाओं में आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर वर्षा जल संचयन की प्रणाली स्थापित की गई है। इससे न केवल भूजल स्तर में सुधार होगा बल्कि पानी की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। सरकार की तरफ से ये पहल सराहनीय है और अन्य राज्यों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक रोहित छाबड़ा, 1 प्लाट नं0 104 ब्लॉक 109 फेस 3 , बालाजी अपॉर्टमेंट देहराखास डीडीएन बालाजी अपॉर्टमेंट, देहरादून उत्तराखंड द्वारा प्रकाशित एवं डी.जी. प्रिंट 48/1 घोसी गली, देहरादून द्वारा मुद्रित। सम्पादकः रोहित छाबड़ा मोबः- 7417010666, सह संपादक - आरूषी सुंदरियाल 8126666064 कार्यकारी सम्पादक- हिमांशु छाबड़ा फैक्सः- 0135-2721716 कानूनी सलाहकारः अमित गोदियाल, आर.एन.आई. नं. U.T.T.H.I.N. 2010/32729
Email: editor.newsdetail@gmail.com समस्त विवाद, देहरादून न्यायलय के अधीन ही होंगे।